भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2095
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और झारखण्ड में नये केन्द्रीय विद्यालय

2095. **श्री बाबू सिंह कुशवाहाः**
श्री के गोपीनाथः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
डॉ. एम.के.विष्णु प्रसादः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय क्षेत्र, तमिलनाडु के विभिन्न जिलों और झारखण्ड के गोड्डा संसदीय क्षेत्र में नए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) तमिलनाडु में नए केन्द्रीय विद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित देश में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा आवंटित/स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) तमिलनाडु में नए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना में देरी के क्या कारण हैं और इन केन्द्रीय विद्यालय में कक्षाएं शीघ्र शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) नए केंद्रीय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय विद्यालय मुख्य रूप से रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थान (आईएचएल) सहित स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं, ताकि पूरे देश में शिक्षा का एक साझा कार्यक्रम प्रदान किया जा सके। नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं, जिसमें मानदंडों के अनुसार नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि और अस्थायी आवास सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शामिल है। केंद्रीय विद्यालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/जिले के मानदंडों के आधार पर नहीं खोले जाते हैं।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में नए केवि खोलने के लिए 05 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें जौनपुर जिले में 01 प्रस्ताव और तमिलनाडु राज्य में नए केवि खोलने के लिए 02 प्रस्ताव शामिल हैं। झारखंड के गोड्डा संसदीय क्षेत्र में नया केवि खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए आयोजक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर जांच/प्रक्रिया की जाती है, तथा उसके बाद विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) को प्रतिवर्ष तीन अलग-अलग लेखा शीर्षों अर्थात वेतन, सामान्य और केंद्रीय विद्यालयों (केवि) को खोलने और चलाने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के तहत अनुदान के रूप में बजट संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। केविसं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार निधि आवंटित नहीं की जाती है। पिछले पांच वित्त वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केविसं को आवंटित निधि इस प्रकार है: -

(रु. करोड़ में)

वर्ष	**आवंटित निधियां**
2019-20	6331.40
2020-21	6437.68
2021-22	6800.00
2022-23	7461.25
2023-24	8500.00
2024-25 (ब.अ.)	9302.67

*****